Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January 2024 5(1), 1356–1363

STUDY OF THE IMPACT OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM SCHEME ON THE ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF PANDO TRIBES

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का पण्डो जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन

Rakesh Kumar Gupta [1], Anil Kumar Kushwaha [2]

[1] Associate Professor, Economics Research Scholar Economics, Department of Social Science (Economics), DR. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
[2] Research Scholar Economics, Department of Social Science (Economics) DR. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

ABSTRACT

English: The tribes of Chhattisgarh state are known for their distinct culture, language, social structure and customs. A large part of the population of Chhattisgarh is made up of tribal communities, which makes the cultural diversity and traditions of this state special. Majumdar, D.N. (2020) found in his study that efforts are being made to introduce the major tribes of Chhattisgarh and their cultural heritage, lifestyle, challenges and development. Chhattisgarh is an emerging state located in the middle of India, Chhattisgarh was formerly a part of Madhya Pradesh state and was separated on 1 November 2000 and formed as the twenty-sixth state. According to Dhruv, Toshni (2018), at the time of formation of Chhattisgarh state, there were a total of 16 districts in the state, currently after the announcement of the Chief Minister, there are a total of 33 districts. According to the 2011 census, the total population of Chhattisgarh state was 2,55,45,198, in which 42 types of scheduled tribes are residing in Chhattisgarh state. Nisha Kumari (2016) told that the population of scheduled tribes in Chhattisgarh state is 78,22,902, according to the 2011 census, in which the number of men is 38,73,191 and the number of women is 39,49,711. Scheduled tribes constitute 6.2 percent of the total population of the country and 30.60 percent of the total population of the state. The sex ratio among scheduled tribes is 1020 and the literacy rate is 50.11 percent, in which the male literacy rate is 58.85 percent and the female literacy rate is 41.38 percent.

Hindi: छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, सामाजिक संरचना और रीति-रिवाजों के लिए जानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजातीय समुदायों से बना है, जो इस राज्य की सांस्कृतिक विविधता और परम्पराओं को विशेष बनाता है। मजूमदार, डी.एन. (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों का परिचय और उनकी सांस्कृतिक धरोहर, जीवन शैली, चुनौतियाँ और विकास के प्रयास किए जा रहे है। छत्तीसगढ़, भारत के मध्य में स्थित उदीयमान राज्य है, छत्तीसगढ, पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का हिस्सा रहा एवं 1 नवम्बर 2000 को अलग होकर छब्बीसवें राज्य के रूप में गठित हुआ है। ध्रुव, तोषणी (2018) के अनंसार, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल 16 जिले थे, सम्प्रति मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात् कुल 33 जिले हो गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 42 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ निवास कर रही है। निशा कुमारी (2016) ने बतलाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 78,22,902, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है, इसमें पुरूषों की संख्या 38,73,191 एवं महिलाओं की संख्या 39,49,711 है। देश की कुल जनसंख्या का 6.2 प्रतिशत एवं राज्य की कुल जनसंख्या का 30.60 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 1020 है और साक्षरता दर 50.11 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 58.85 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 41.38 प्रतिशत है।

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3231

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

Keywords: Traditional Lifestyle, Special Backward Tribes and Possibilities of Development of Rural Areas, पारम्परिक जीवन शैली, विषेष पिछड़ी जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाएँ।

1. प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार विविधता पाई जाती है उनमें भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, प्राकृतिक स्थिति एवं जलवायु जैसे घटक विद्यमान हैं, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी ये घटक विद्यमान है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रभाव यहाँ की जनजातियों में परिलक्षित होता है। बेक, वेद प्रकाष (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि देश में कई प्रकार की कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, प्राकृतिक स्थिति एवं जलवायु विद्यमान हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की भी अपनी कला, संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक जलवायु और कई प्रकार की जनजातियाँ भी विद्यमान हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के भी विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनेक प्रावधान दिए गये हैं, इस प्रावधान के फलस्वरूप जनजातियों को कुछ भागों में विभक्त किया गया है, इनमें कुछ विशेष प्रावधान की जनजातियाँ हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। ठाकुर, ममता (2019-20) के अध्ययन के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकता है। मीणा हरिराम (2022) ने बतलाया कि छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ भारतीय जनजातीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, यह राज्य जनजातीय जीवन, संस्कृति, परम्पराओं और उनके इतिहास की समृद्ध धरोहर को अपने में समेटे हुए है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रत्येक शोध कार्य किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अनुसन्धानकत्र्ता ने अपने शोध कार्य करने के पूर्व विविध प्रकार के उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया है तदुपरान्त अपने भावी शोध रूपी इमारत की रूपरेखा का निर्धारण किया। अध्ययनकर्ता ने पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत जनजातियों के सन्दर्भ में शोध कार्य का अभाव है और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में निवासरत जनजातियों पर शोधकार्य का नितान्त अभाव है।

- छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का पण्डो जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावों का अध्ययन करना।

3. अध्ययन की परिकल्पनाएँ

अध्ययनकर्ता ने उपलब्ध साहित्यों का अध्ययन करने के उपरान्त सर्वप्रथम शोध अन्तराल का चिह्नांकन किया तदुपरान्त अपने भावी शोध पत्र की रूपरेखा निर्धारित की। अध्ययनकर्ता ने अध्ययन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोध पत्र में निम्न शोध परिकल्पना की है जिसका अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययनकर्ताद्वय द्वारा किया गया है -

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का पण्डो जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।

4. अध्ययन की सीमाएँ

प्रत्येक शोध पत्र कार्य में किसी पूर्व शोध का पुनः अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा भी शोध विषय की विशालता को देखते हुये समय सीमा की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर अध्ययन हेतु कुछ सीमाओं का निर्धारण किया है ताकि शोधार्थी द्वारा चयनित विषय को समय पर पूर्ण किया जा सके। शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। द्वितीयक समंकों के संकलन के लिये पिछले पाँच वर्षों 2019-20 से 2023-24 के प्रकाषित एवं अप्रकाषित आँकड़ें मुख्यरूप से प्रयुक्त किये गये है। इसके अलावा आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन के लिये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न पैकेज का अनुप्रयोग किया गया है।

5. नमूनाकरण विधि

प्रस्तुत शोध में अनुसन्धानकर्ता ने एक मौलिक तकनीक उपयोग में लायी है जिसमें बड़ी आबादी में से एक छोटे समूह अथवा नमूने का चयन किया है, ताकि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। शोध पद्धतियों की यह विधि आवष्यक है क्योंकि समय, लागत और संसाधनों जैसी बाधाओं

के कारण पूरी आबादी का अध्ययन करना अक्सर अव्यावहारिक हो जाता है, अतः अनुसन्धानकर्ता ने नमूनाकरण विधि का उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में किया हैं। तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक जनसंख्या से चयनित संख्या में न्यादर्श लेने के लिये अनुसन्धानकर्ता ने प्रतिदर्श चयन के स्लोविन्स (Slovin's) सूत्र का अनुप्रयोग किया है, जिसके अनुसार,

$$n = \frac{N}{(1 + N * e^2)}$$

जहाँ,

n = प्रतिदर्ष का आकार

N = कुल जनसंख्या का आकार

e = विष्वास स्तर

अनुसन्धान कार्य में शोधार्थी के द्वारा विकासखण्ड वाड्रफनगर एवं रामचन्द्रपुर के कुल 89 ग्राम पंचायत हैं जिसमें पण्डो जनजातियों की कुल संख्या 23,680 है। अतः उपरोक्त सूत्र के अनुसार 23,680 जनसँख्या के लिए 0.5 विष्वास स्तर पर प्रतिदर्ष का आकार होगा -

$$n = \frac{23680}{(1 + 23680 * 0.05^2)}$$

$$n = 393 - 3554$$

सार्थक संख्या के नियमानुसार इस समंक को पूर्ण करने पर दत्र 400 की संख्या आती है जिसे अनुसन्धानकर्ता ने इस शोध अध्ययन के प्रतिदर्ष आकार के रूप में स्वीकृत किया है।

6. शोध विषय का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का पण्डो जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सार्थक प्रभाव पड़ रहा है-

तालिका क्रमांक 01 - खाद्यान्न व्यवस्था के माध्यमों का विवरण						
उत्तर संकेतन	कृषि के माध्यम से	राशन की दुकान (बी.पी.एल. कार्ड) द्वारा	राशन की दुकान (ए.पी.एल. कार्ड) द्वारा	खाद्यान्न खरीदकर	अन्य माध्यमों से	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	17	332	13	28	10	**400**
फीसदी	4-25	83-00	3-25	7-00	2-50	**100**
प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त						

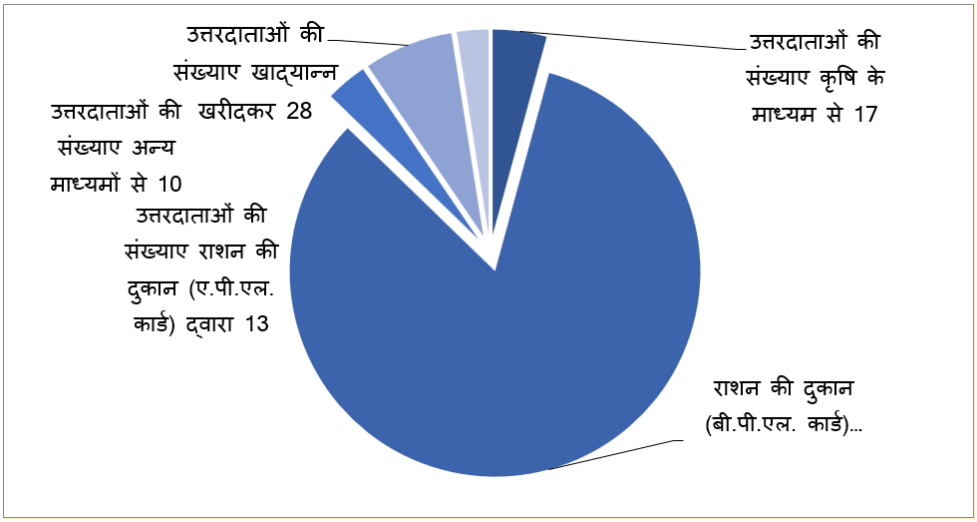

आरेख क्रमांक 01- खाद्यान्न व्यवस्था के माध्यमों का विवरण

अध्ययन क्षेत्र के पण्डो जनजाति के लोग किस माध्यम से खाद्यान्न की व्यवस्था करते है, पूछे गये इस प्रष्न के उत्तर के लिए कुल 400 उत्तरदाताओं में से 4.25 फीसदी ने कृषि के माध्यम से, 83 फीसदी राषन की दुकान (बी.पी.एल. कार्ड) द्वारा, 3.25 फीसदी राषन की दुकान (ए.पी.एल.कार्ड) द्वारा, 7 फीसदी खाद्यान्न खरीद कर एवं 2.50 फीसदी अन्य माध्यमों से भोजन हेतु खाद्यान्न व्यवस्था करना बतलाया है। इस अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र के 4.25 फीसदी पण्डो परिवार के पास कृषि कार्य करने हेतु भूमि एवं अन्य संसाधन उपलब्ध है, सर्वाधिक 83 फीसदी पण्डो परिवार शासन के खाद्यान्न व्यवस्था राषन दुकान (बी.पी.एल. कार्ड) का उपयोग कर रहे हैं, 3.25 फीसदी उत्तरदाता ए.पी.एल. कार्डधारक हैं व 7 फीसदी अनाज अन्य दुकानों या सेठ साहूकारों से खरीद कर उपयोग करते हैं, ऐसे पण्डो परिवार जो सम्पन्न या शासकीय कर्मचारी वर्ग के हैं और 2.50 फीसदी उत्तरदाता अन्य माध्यमों से भोजन व्यवस्था करते हैं वे अपने गाँव या आस-पास के गाँव में देवी-देवता पूजा, ग्राम देवता पूजा के बदले प्राप्त दान या भिक्षावृत्ति के माध्यम से खाद्य सामग्री व्यवस्था करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 86.25 फीसदी उत्तरदाताओं के लिए शासन की खाद्यान्न योजना भोजन व्यवस्था के लिए कारगर है।

तालिका क्रमांक 02 -सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) प्रारम्भ होने से पूर्व की खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था विवरण					
उत्तर संकेतन	उत्कृष्ट के लिए	अच्छा के लिए	औसत से कम के लिए	असन्तोषजनक के लिए	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	12	71	210	39	68
फीसदी	3-00	17-75	52-50	9-75	17-00
प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त					

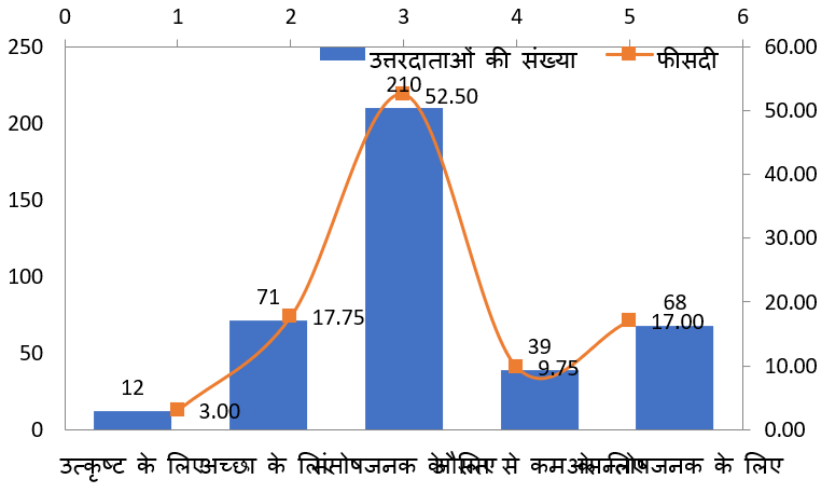

आरेख क्रमांक 02 -सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) प्रारम्भ होने से पूर्व की खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था विवरण

तालिका क्रमांक 03 -वर्तमान में राशन की दुकान से खाद्यान्न सामग्री की सहज प्राप्ति के स्तर का विवरण					
उत्तर संकेतन	उत्कृष्ट के लिए	अच्छा के लिए	औसत से कम के लिए	असन्तोषजनक के लिए	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	44	249	49	37	21
फीसदी	11-00	62-25	12-25	9-25	5-25
प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त					

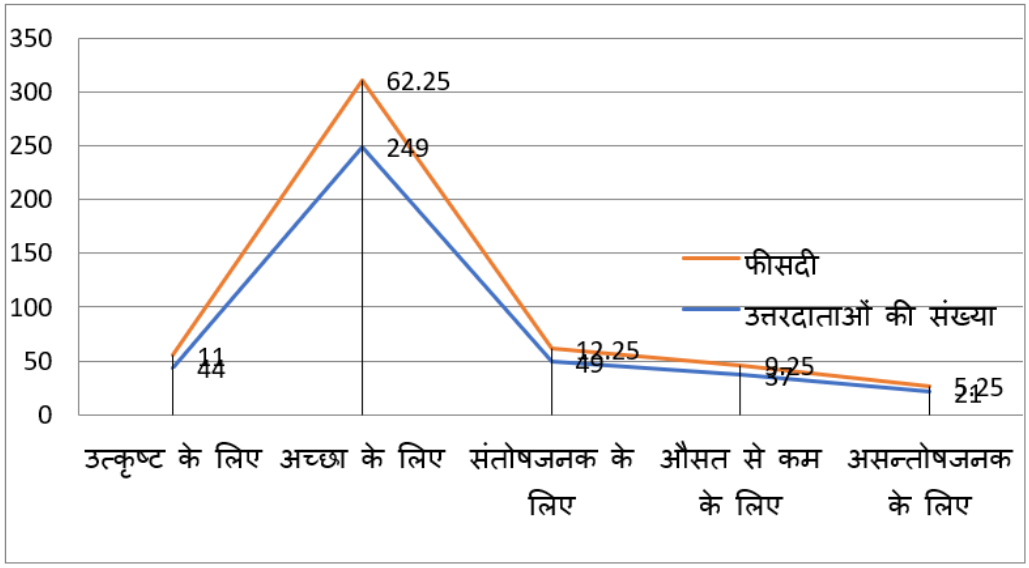

आरेख क्रमांक 03 -वर्तमान में राशन की दुकान से खाद्यान्न सामग्री की सहज प्राप्ति के स्तर का विवरण

''खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा पीडीएस व्यवस्था प्रारम्भ से पूर्व एवं बाद (वर्तमान) में राषन दुकान से खाद्य सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था एवं सहजता का स्तर व्यक्त करें'' के सन्दर्भ में अनुसंधानकत्र्ता ने उत्तरदाताओं से एकत्र आँकड़ों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किया -

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 में कुल 400 उत्तरदाताओंद्वारा उत्कृष्ट के लिए 3 फीसदी, अच्छा के लिए 17.75 फीसदी, संतोषजनक के लिए 52.50 फीसदी, औसत से कम के लिए 9.75 फीसदी एवं असन्तोषजनक के लिए 17 फीसदी उत्तर प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त परिणाम के आवृत्तियों का सांख्यिकीय परिकलन निम्नानुसार प्राप्त किया गया।

$$= 12X5+71X4+210X3+39X2+68X1 = 1120$$

लिकर्ट पैमाने के प्राप्त आवृत्तियों का मान निम्नानुसार प्राप्त किया गया।

$$= \frac{1120}{400} = 2.80$$

इसी प्रकार उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 में कुल 400 उत्तरदाताओं के परिवार द्वारा उत्कृष्ट के लिए 11 फीसदी, अच्छा के लिए 62.25 फीसदी, संतोषजनक के लिए 12.25 फीसदी, औसत से कम के लिए 9.25 फीसदी एवं असन्तोषजनक के लिए 5.25 फीसदी उत्तर प्राप्त किया गया है।

तालिका क्रमांक 03 परिणाम के आवृत्तियों का सांख्यिकीय परिकलन निम्नानुसार प्राप्त किया गया।

$$= 44X5+249X4+49X3+37X2+21X1 = 1458$$

प्राप्त आवृत्तियों का माध्य मान निम्नानुसार प्राप्त किया गया।

$$= \frac{1458}{400} = 3.645$$

खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा पीडीएस व्यवस्था प्रारम्भ हाने से पूर्व एवं पश्चात् (वर्तमान) राषन दुकान से खाद्य सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था एवं सहजता का स्तर स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकीय विधि का अनुसरण करते हुए उत्तर संकेत के लिए इस प्रकार अंक स्केल प्रदाय किया गया है दोनो चरो के माध्य में $= 3.645 - 2.80 = 0.845$ अन्तर पाया गया। इससे स्पष्ट है कि खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा पीडीएस व्यवस्था प्रारम्भ हाने से पूर्व एवं बाद (वर्तमान) में राषन दुकान से प्राप्त खाद्यान्न के गुणवत्ता स्तर में वृद्धि पाई गई।

Test Statistics

	(पी.डी.एस.) प्रारम्भ से पूर्व	वर्तमान में खाद्यान्न सामग्री प्राप्त की सहजता
Chi-Square	292.875[a]	451.850[a]
df	4	4
Asymp. Sig.	.000	.000

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 80.0.

उपरोक्त काई-वर्ग तालिका द्वारा भी अवलोकन किये जाने पर उल्लेखनीय अन्तर पाया गया है। प्रस्तुत तालिका में पीडीएस प्रारम्भ के बाद एवं पूर्व की सहजता से मूल्यांकन करने के लिए तुलना की गई है पहले कॉलम में काई-वर्ग 292.875 और दूसरे में 451.850 है, जिसमें दोनों के लिए स्वतंत्रता की कोटि (Degrees of Freedom) $df = 4$ है। दोनों ही परीक्षणों का आसिम्पटोटिक सिग्निफिकेंस (Asymptotic Significance)p-value =.000 है, जो दर्शाता है कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।

तालिका क्रमांक 04 -आपातकाल अथवा आपदा की स्थिति (जैसे - कोविड-19) में सार्वभौम वितरण प्रणाली योजना की उपादेयता का विवरण					
उत्तर संकेतन	उत्कृष्ट के लिए	अच्छा के लिए	औसत से कम के लिए	असन्तोषजनक के लिए	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	63	249	41	24	23
फीसदी	15-75	62-25	10-25	6-00	5-75
प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त					

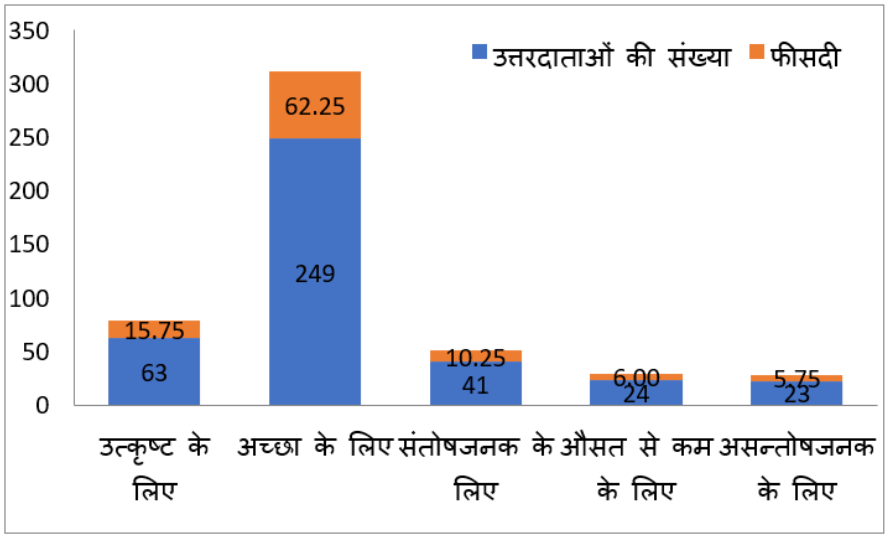

आरेख क्रमांक 04 -आपातकाल अथवा आपदा की स्थिति (जैसे- कोविड-19) में सार्वभौम वितरण प्रणाली योजना की उपादेयता का विवरण

आपातकाल अथवा आपदा (कोविड-19 जैसे) की स्थिति में सार्वभौम वितरण प्रणाली योजना की उपादेयता से कहाँ तक सहमत है।

इस प्रष्न के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए कोरोनाकाल (कोविड-19) में शासन द्वारा निःषुल्क राषन सामग्री प्रदाय करने की योजना चलाई गई थी इस योजना के लिए पण्डो परिवारों द्वारा उपादेयता के लिए, 15.75 फीसदी उत्तरदाताओं द्वारा उत्कृष्ट,

62.25 फीसदी अच्छा, 10.25 फीसदी संतोषजनक, औसत से कम के लिए 6 फीसदी और असन्तोषजनक के लिए 5.75 फीसदी उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि लगभग 88.25 फीसदी उत्तरदाताओं द्वारा आपातकाल में सार्वभौम वितरण प्रणाली की उपादेयाता को स्वीकार किया और 11.75 फीसदी ने यह माना की उचित मूल्य दूकान संचालक मनमानी करते थे या कुछ लोगों में इसके लिए जानकारी का आभाव पाया गया। इससे स्पष्ट होता होता है कि आपातकाल अथवा आपदा (कोविड-19 जैसे) कि स्थिति में सार्वभौम वितरण प्रणाली योजना की उपादेयता महत्वपूर्ण रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पण्डो परिवार के सामाजिक जीवन पर प्रभाव का स्तर व्यक्त करें।

उपरोक्त प्रष्न के माध्यम से पण्डो परिवार के सामाजिक जीवर स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किस स्तर तक प्रभाव पड़ रहा है,इसके लिए अध्ययन क्षेत्र के 400 उत्तरदाताओं में से, 9.75 प्रतिषतउत्तरदाताओं द्वारा उत्कृष्ट के लिए, 67.75 प्रतिषत अच्छा के लिए, 11.25 प्रतिषत संतोषजनक के लिए, औसत से कम के लिए 7.25 प्रतिषत और असन्तोषजनक के लिए 4.00 प्रतिषत ने अपना उत्तर प्रकट किया। तालिका क्रमांक 4.09 व आरेख क्रमांक 4.09 में प्रदर्षित है -

तालिका क्रमांक 05 -सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पण्डो परिवार के सामाजिक जीवन पर प्रभाव का स्तर					
उत्तर संकेतन	उत्कृष्ट के लिए	अच्छा के लिए	औसत से कम के लिए	असन्तोषजनक के लिए	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	39	271	45	29	16
फीसदी	9-75	67-75	11-25	7-25	4-00
प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त					

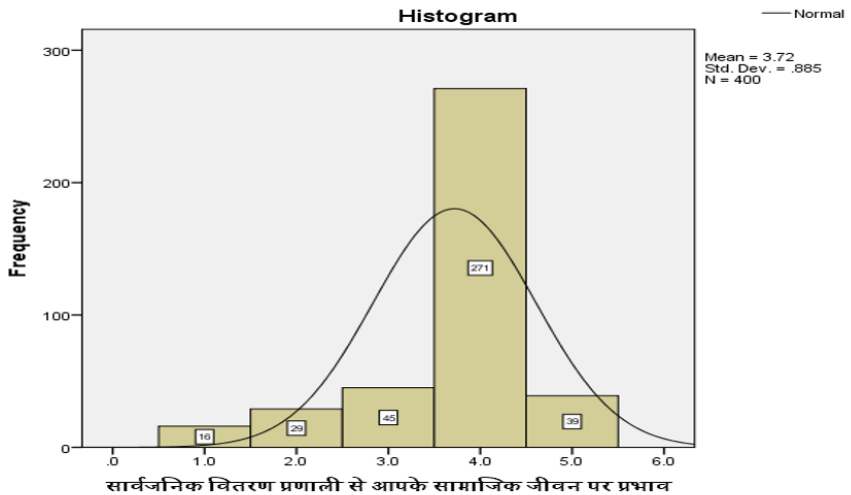

आरेख क्रमांक 05 -सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पण्डो परिवार के सामाजिक जीवन पर प्रभाव का स्तर

उपरोक्त तालिका एवं हिस्टोग्राम ग्राफ से स्पष्ट है कि कुल उत्तदाताओं के प्रतिषत का बड़ा भाग, 88.75 प्रतिषत ने उत्तर में बतलाया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आनाज उपलब्ध हो जाने से समय पर भोजन उपलब्ध हो जाता है जिससे अन्य स्त्रोत से भोजन जुटाने का समय बचत होता है उस समय पर अन्य कार्यों कर लेते हैं और निरंतर समय पर भोजन मिलने अच्छा पोषण मिलता है। किन्तु 11.25 प्रतिषत उत्तरदाता आज भी जानकारी के आभाव में योजनाओं से वंचित हो जाते हैं या योजना का उपयोग करने के वावजूद व्यक्त करने में असमर्थ हैं।उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पण्डो जनजातियों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।

तालिका क्रमांक 06 -पण्डो जनजाति पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आर्थिक प्रभाव का विवरण					
उत्तर संकेतन	उत्कृष्ट के लिए	अच्छा के लिए	औसत से कम के लिए	असन्तोषजनक के लिए	योग
उत्तरदाताओं की संख्या	39	271	45	29	16
फीसदी	9-75	67-75	11-25	7-25	4-00

प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त

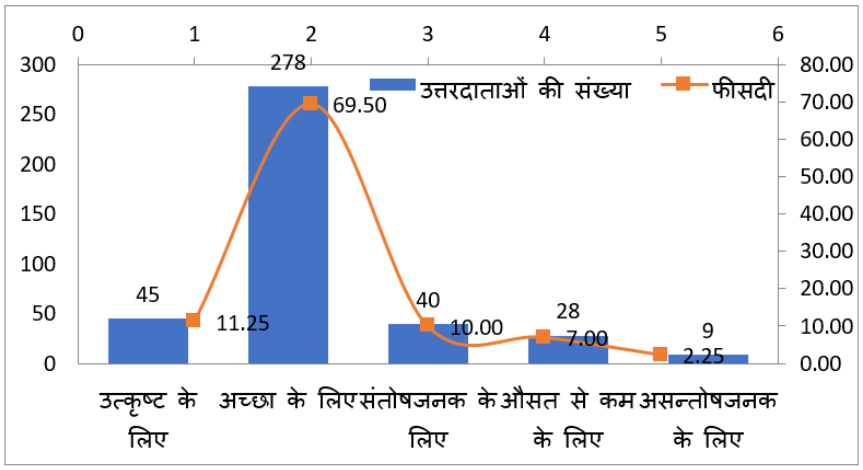

आरेख क्रमांक 06 - पण्डो जनजाति पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आर्थिक प्रभाव का विवरण

शोधार्थी द्वारा जानने का प्रयास किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पण्डो जनजातियों पर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त उत्तर उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट किया गया है कि चयनित 400 उत्तरदाताओं के परिवार में से उत्कृष्ट के लिए 45 (11.25 प्रतिशत), अच्छा के लिए 278 (69.50 प्रतिशत), संतोषजनक के लिए 40 (10 प्रतिशत), औसत से कम के लिए 28 (7 प्रतिशत) तथा असन्तोषजनक के लिए 9 (2.25 प्रतिषत) उत्तरदाताओं द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 90.75 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने माना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का आर्थिक रूप से बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। किन्तु 9.25 प्रतिषत उत्तर औसत से कम एवं असन्तोषजनक के लिए प्राप्त हुए जो व्यक्त करता है कि इस योजना को अपने आर्थिक प्रभाव या लाभ की दृष्टि से नहीं देखते या योजना के प्रति जागरूकता का अभाव है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

ध्रुव, तोषणी (2018). कमार जनजाति के विकास प्रकोष्ठ के योगदान का विष्लेषण (छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के विषेष सन्दर्भ में) पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, पं. रविषंकर विष्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

निशा कुमारी (2016). छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वसहायता समूह का योगदान (धमतरी जिला के नगरी विकासखण्ड के विषेष सन्दर्भ में) पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, पं. रविषंकर विष्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बेक, वेद प्रकाष (2017). पण्डो जनजाति के विकास मे शासकीय योजनाओं की भूमिका (छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला के ओड़गी विकासखण्ड की विषेष सन्दर्भ में), पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, पं. रविषंकर विष्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

ठाकुर, ममता (2019-20). छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित, (दुर्ग-भिलाई नगर में) पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, पं. रविषंकर विष्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

मजूमदार, डी.एन. (2020). एन इन्ट्रोडक्सन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मयूर बुक्स, दिल्ली, ISBN-10. 817198147X, ISBN-13. 978-8171981472.

मीणा हरिराम (2022). आदिवासी दुनिया में आदिवासी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, वसंत कुंज, नई दिल्ली, भारत, ISBN No. 978-81-237-6672-0.